

उत्तरांचल शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग
संख्या 627-11/XI/06/05-मु0म0ध0/2005
देहरादून, दिनांक 22 मई 2006
कार्यालय झाप

उत्तरांचल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार प्रदान कराने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप वर्ष 2006-07 में " उत्तरांचल ग्रामीण स्वरोजगार मिशन " नामक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की जा रही है। यह योजना प्रदेश के सभी 13 जनपदों में एक साथ प्रारम्भ की जा रही है। योजना के संचालन हेतु निम्नानुसार मार्ग-निर्देशों जारी किये जा रहे हैं:-

1-प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों (स्व-रोजगारियों) को बैंक ऋण तथा अनुदान के माध्यम से आय सृजक परिसम्पत्तियाँ मुहैया कराकर उन्हें तीन वर्ष के अन्दर गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999-2000 से संचालित की गई है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों में अभिवृद्धि हेतु " उत्तरांचल ग्रामीण स्वरोजगार मिशन " नामक योजना हेतु रुपये 2600.00 (रुपये छबीस करोड़) स्वीकृत करने की घोषणा की गई है। यह योजना स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तर्ज पर ही समूह पद्धति से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की पूरक योजना के रूप में संचालित होगी।

"उत्तरांचल स्वरोजगार मिशन " योजना स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के मानकों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग -निर्देशों के अनुसार ही संचालित की जायेगी। योजनान्तर्गत महिला सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु क्षमता विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ, अध्ययन, भ्रमण कार्यक्रम, कार्यशालाओं का आयोजन तथा विपणन हेतु मेला-प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जायेगा।

योजनान्तर्गत नये समूहों का गठन भी किया जा सकेगा। तथा वर्ष 2002 के सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित बी0पी0एल0 परिवार भी पात्र होंगे।

2- उद्देश्य

योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले के परिवारों (स्व-रोजगारियों) को सामाजिक गतिशीलन आधारित समूह पद्धति द्वारा बैंक ऋण तथा अनुदान के माध्यम से आय सृजक परिसम्पत्तियाँ मुहैया कराकर उन्हें तीन वर्ष के अन्दर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना अर्थात् एक परिवार की शुद्ध मासिक आय कम से कम रु. 2000.00 हो जाये। बल सूक्ष्म

5- प्रमुख गतिविधियों का चयन

योजना की सफलता क्रियाकलापों के चयन पर निर्भर करती है। क्रियाकलापों का चयन स्थानीय संसाधनों, अभिरुचि तथा लोगों की दक्षता, सामाजिक पूँजी पर आधारित उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय से सम्बन्धित क्रिया कलापों के आधार पर किया जायेगा।

6- स्वयं सहायता समूह

योजना की नीति गरीबों को संगठित करने की है। इससे गरीबों के पास अपनी सहायता स्वयं करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। सामाजिक संघटन गरीबों को अपने स्वयं के संगठन (स्व-सहायता समूह) बनाने में समर्थ बनाता है।

7-स्वयं सहायता समूहों की संरचना

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों का एक समूह है जो गरीबी के उन्मूलन के लिये स्वयं को समूह के सदस्यों के रूप में संगठित करने के लिये अपनी सेवा अर्पित करता है।

8-स्वयं सहायता समूह गठन का उद्देश्य

स्थानीय संसाधनों/क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के लिये जागरूक बनाना, ग्रामीण महिलाओं एवं निर्धनों को आत्मनिर्भर बनाना, समान कार्य एवं रुचि के लोगों को एक साथ संगठित कर आय वर्धक कार्यक्रम चलाना, स्वरोजगारियों एवं बैंको के बीच विश्वनीयता एवं आत्मविश्वास कायम करना।

एक स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 लोगों को शामिल किया जा सकता है किन्तु दुर्गम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में यह संख्या 05 से 20 तक होगी। लघु सिंचाई के मामले में तथा विकलांग व्यक्तियों के मामले में यह संख्या न्यूनतम पांच हो सकती हैं। समूह के सभी सदस्य बी0पी0एल0 होंगे तथापि ए0पी0एल0 परिवारों की सदस्यता के संबंध में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के मार्ग निर्देशों के प्राविधान लागू होंगे। समूह स्वयं को चलाने के लिये आचार संहिता (समूह प्रबन्ध मानदंड) बनायेगा। समूह के सदस्यों को नियमित बचतों के माध्यम से अपनी प्रारम्भिक पूँजी बनानी होगी। सदस्यों को बचत की मात्रा का निर्णय स्वयं लेना होगा, जो कम से कम रु. 30.00 प्रतिमाह हो। समूह की प्रारम्भिक पूँजी सदस्यों को आपसी ऋण देने में प्रयुक्त की जायेगी। समूहों द्वारा बैंक बचत खाता स्थानीय बैंको में खोले जायेंगे। समूह कार्यवृत्त पुस्तिका, उपस्थिति रजिस्टर, ऋण खाता, सामान्य खाता, कैश बुक, बैंक पासबुक तथा वैयक्तिक पासबुक जैसे सामान्य मूल रिकार्डों को रखेगा। प्रत्येक विकास खण्ड में नये समूहों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत समूह महिलाओं के ही गठित किये जायेंगे जिसमें अनुसूचित जाति /जन जाति के कमशः 18 एवं 3 प्रतिशत समूह अनिवार्य रूप से गठित किये जायेंगे।

विधिवत रख रखाव, द्वितीय मानकीकरण के पश्चात समूहों के ऋण प्रार्थना पत्र बैंक शाखाओं को प्रस्तुत करना तथा बैंकों से ऋण वितरण कराकर परिसम्पत्तियों का क्रय कराना, समूहों के उत्पादकों की धिक्की परिसंधों के माध्यमों से विपणन केन्द्रों तक भिजवाना, समय-समय पर परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन तथा समूहों के सदस्यों के गतिविधियों के संचालन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण कराना योजना सभी समूहों का बाहरी एवं आंतरिक संस्थाओं से मूल्यांकन यथावश्यक कराया जावेगा

13- अन्य बिन्दु :- यह सुनिश्चित किया जाये कि अन्य रोजगार परक योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा । विकास खण्ड स्तर, जिला स्तर तथा आयुक्त ग्राम्य विकास स्तर पर योजना के सम्बन्ध में लाभार्थियों इन्वेस्ट्री तैयार की जाये तथा उसे हमेशा अद्यावधिक पूर्ण रखा जाये । जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर योजना के संचालन हेतु विशेष प्रचार प्रसार किया जाये ताकि योजना के संबंध में जनता को सही जानकारी एवं लाभ प्राप्त हो सके ।

14-विकास खण्ड/डी०आर०डी०ए० स्तर पर गुणात्मक पडताल:-

विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों तथा जिला ग्रामीण विकास अभिरक्षण के अधिकारियों द्वारा योजना के निरीक्षण के लिये एकरूप तंत्र बनाने एवं परिसम्पत्ति के भौतिक सत्यापन के साथ आय अर्जन की दृष्टि से समूहों के स्वरोजगारियों की प्रगति के लिए विभिन्न स्तर से अधिकारियों द्वारा समूहों का स्थलीय सत्यापन मानकों के अनुरूप किया जाना ।

1. मुख्य विकास अधिकारी/अधिसासी निदेशक,	प्रतिमाह 10
2. परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए.,	प्रतिमाह 20
3. जिला विकास अधिकारी,	प्रतिमाह 20
4. अपर परियोजना निदेशक,	प्रतिमाह 20
5. सहायक परियोजना निदेशक एवं परियोजना अर्थशास्त्री	प्रतिमाह 40
6. उपजिलाधिकारी,	प्रतिमाह 20
7. खण्ड विकास अधिकारी,	प्रतिमाह 20
8. सहायक विकास अधिकारी,	प्रतिमाह 20 "

पी०के०महान्ति
सचिव


संख्या 627-11/XI/06/05-मु०मं०घो०/2005 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित :-

1:- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव उत्तरांचल शासन ।

- 2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल पौड़ी ।
- 3-आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाँयू मण्डल ।
- 4-समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
- 5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी / अधिशासी निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरांचल ।
- 6- समस्त परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरांचल ।
- 7- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल देहरादून ।
- 8- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तरांचल ।
- 9- निजी सचिव-मुख्यमंत्री उत्तरांचल को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
- 10- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 ।
- 12- नियोजन विभाग ।
- 13- समाज कल्याण विभाग ।
- 14- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से ,


(ललित मोहन आर्य)

उप सचिव

9-स्वयं सहायता समूहों का मानकीकरण

समूह गठन की अवस्था बारह माह की होगी। प्रारम्भ से प्रथम छः माहों में स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य एक व्यवहार्य समूह के रूप में विकसित होना होगा तदनुसार छः माह के अन्त पर प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के विकास की प्रथम अवस्था में उद्देश्यों के प्रसंग पर मानकीकरण किया जायेगा। प्रथम मानकीकरण में सफल होने पर रिवाल्विंग फण्ड एवं ऋण साख सीमा उपरीवर्णित मानकों के अनुसार स्वीकृत की जायेगी।

10- द्वितीय मानकीकरण एवं बैंक वित्त पोषण :-

समूहों द्वारा द्वितीय मानकीकरण को पार करने के पश्चात समूह को बैंक ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्त पोषित किया जायेगा। बैंक ऋण तथा अनुदान 3 : 1 की दर पर स्वीकृत किया जायेगा तथा समूह के प्रति स्वरोजगारी न्यूनतम रु0 0.30 लाख की दर से रु0 3.00 लाख की औसत से ऋण स्वीकृत किया जायेगा तथा अनुदान धनराशि ऋण के सापेक्ष प्रति सदस्य अधिकतम रु0 10000.00 की दर से, किन्तु रु0 1.25 लाख से अनधिक प्रति समूह होगी यह धनराशि स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या जो भी कम हो देय होगी। ऋण की अधिकतम सीमा परियोजना प्रस्ताव पर निर्भर करेगी जिसकी बारम्बारता परियोजना की सफलता पर आधारित होगी। अनुमन्य अनुदान का समायोजन Back ended subsidy के रूप में होगा इस धनराशि पर न तो ब्याज लिया जायेगा और न ही ब्याज दिया जायेगा।

11-कौशल विकास प्रशिक्षण

प्रथम मानकीकरण से पूर्व आधारभूत अभिरुचि प्रशिक्षण दिया जायेगा तत्पश्चात समूह द्वारा चुनी हुई क्रियाकलापों/ गतिविधियों के लिये जिन स्वरोजगारियों को अतिरिक्त दक्षता विकास/दक्षता उन्नयन की आवश्यकता है उनके लिये उपयुक्त कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जो सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं, रेखीय विभागों और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा प्रदान किया जायेगा।

12-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:-

शासन एवं निदेशालय स्तर पर योजना का प्रत्येक माह अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य होगा, इसी प्रकार मण्डलीय एवं जनपदीय समीक्षा बैठकों में भी योजना की उत्तरोत्तर सफल कार्यान्वयन केन्द्रित समीक्षाएँ की जायेंगी। विभाग के खण्ड स्तरीय, ग्राम स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रत्येक माह समूहों की बैठकों में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जिसमें समूहों की गति विधियों को संचालित करने की जानकारी, बचत की धनराशि का आपसी ऋण वितरण व उसकी वसूली, प्रथम मानकीकरण, कौशल विकास प्रशिक्षण, चकीय कोष का उत्पादकता सम्बन्धी कार्यों हेतु आपसी ऋण वितरण तथा उसकी मासिक वसूली तथा समूहों के अभिलेखों का

वित्त की प्रभावशीलता से जनित उसकी अनुमन्यता एवं ग्राह्यता की बारम्बारता, आत्म निर्भरता हेतु वित्त पोषण से, आय सृजक परिसम्पत्ति व सेवाओं के अर्जन एवं उसके सदुपयोग, सूक्ष्म एवं लघु वित्त की सामयिक वापसी एवं पुनःवित्तपोषण पर दिया जायेगा।

3-संसाधन

योजना शतप्रतिशत राज्य पोषित है जिसमें समूहों की बचत के समतुल्य राशि चकीय कोष के रूप में देय होगी जो रु. 5000.00 से अन्यून एवं रु. 10,000.00 से अनधिक होगी। ऋण साख सीमा सम्बन्धित बैंकों द्वारा प्रथम ग्रेडिंग के उपरान्त समूह की बचत के गुणोंक से एक बार में अधिकतम चार गुना राशि के समतुल्य स्वीकृत की जायेगी। प्रशिक्षण एवं अवस्थापना मद पर व्यय स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा, किन्तु इस योजना में प्राविधानित राशि तभी व्यय की जायेगी जब स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के इन मदों में उपलब्ध निर्धारित धनराशि व्यय की जा चुकी हो।

योजनान्तर्गत अधिकतम 5 प्रतिशत धनराशि मा0 मुख्यमंत्री जी की धोषणा के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों के विकास खण्ड, जनपदीय एवं राज्य स्तरीय सम्मेलन, सर्वेक्षण, अध्ययन एवं मूल्यांकन, समूहों के अध्ययन भ्रमण, सर्वश्रेष्ठ समूहों को पुरस्कार तथा जनपदों/कर्मियों के प्रोत्साहन/पुरस्कार हेतु मात्राकृत की जा सकेगी। इस योजनान्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के समूहों को भी प्राथमिकतानुसार पुरस्कृत किया जा सकेगा।

4-विशिष्टताएँ

उत्तरांचल ग्रामीण स्वरोजगार मिशन योजना एक ऋण-सह-अनुदान कार्यक्रम है। योजना लघु उद्यमों का एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू शामिल हैं। जैसे- ग्रामीण गरीबों के स्वयं सहायता समूहों का गठन तथा उनकी क्षमता का विकास, सामुहिक क्रियाकलापों की योजना, ढांचा निर्माण, बैंक ऋण तथा विपणन, योजना के अन्तर्गत लघु उद्यमों की स्थापना में समूहगत दृष्टिकोण पर पूर्ण जोर दिया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक विकास खण्ड के लिये वहां उपलब्ध संसाधनों, लोगों की व्यवसायिक दक्षता तथा बाजारों की उपलब्धता पर आधारित 5 से 8 तक प्रमुख कार्यकलापों की पहचान की जायेगी। योजनान्तर्गत एक व्यवस्थित प्रशिक्षण कोर्स के माध्यम से दक्षता विकास पर बल दिया जायेगा। स्व-रोजगारियों द्वारा उत्पादित सामग्री का विपणन स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित समूहों के परिसंघों के माध्यम से किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

योजनान्तर्गत ग्रामीण गरीबों में से बहुत कमजोर परिवारों के समूहों पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा तथा स्वरोजगारियों में से न्यूनतम 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 3 प्रतिशत विकलांगों को लाभान्वित किया जायेगा। कुल में से न्यूनतम 50 प्रतिशत महिलाओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।